

5

आयोजनागत  
संख्या- 606 / 111 (2) / 11-03(बजट) / 2010 टी0सी0-3

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 07 मार्च, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग हेतु आय-व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक मांग में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या- 542/XXXVII(1)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 तथा आपके पत्रांक:- 6937/01 बजट (मार्ग/सेतु कार्य-रा0से0, /2010-11 दिनांक 09-02-2011 के संदर्भ में एवं शा0सं0:- 1716/111(2)/10-03(बजट)/2010 दिनांक 16-04-2010, शासनादेश सं0:- 3754/111(2)/10-03(बजट)/2010 दिनांक 22-07-2010, शासनादेश सं0:- 6376/111(2)/10-03(बजट)/2010 दिनांक 27-10-2010 तथा शासनादेश सं0:- 79/111(2)/10-03(बजट)/2010 दिनांक 13-01-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के मूल आय-व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0:- 22 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में निर्माणाधीन मार्ग (चालू कार्य) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 50.00 करोड़ (₹ पचास करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु, आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-8 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(ii)- आयोजनागत पक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iii)- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों का वरीयता दी जाये।

(iv)- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग- I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

- (v)- इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र:- 187/XXVII(1)/10 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (vi)- उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रक्रियाएँ पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
- (vii)- साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (viii) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर-17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix)- जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (x)- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय एवं प्रथम अनुपूरक के अनुदान सं0- 22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत)-04 जिला तथा अन्य सड़कें-800 अन्य व्यय -03 राज्य सैक्टर -0301 चालू निर्माण कार्य के 24 वृहत्त निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
- (xi)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 913/XXVII(2)/2010 दिनांक: 05 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

( प्रदीप सिंह रावत )  
उप सचिव।

संख्या- 606 (1)/III(2)/11-03(बजट)/2010टी0सी0-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराँय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 8- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
प्रदीप  
( महिमा )  
अनु सचिव।